understand that the law there stipulates that retirement benefits would accrue only after completing forty quarters of employment in the USA. Most Indians hardly stay that long and, therefore, end up contributing that money to the U.S. Treasury, which comes to over one billion dollars annually as I am informed. Incidentally, American professionals in India have no such problems, as they are eligible to withdraw their terminal benefits whenever they change their jobs or leave the country.

The U.S.A. has already signed totalisation pacts with as many as twenty countries permitting repatriation of social security savings, but regrettably, no such pact exists with India up till now.

May I, therefore, urge upon the Government of India to take up the issue with the concerned authorities of the USA and extend reciprocal benefits to the Indian professionals and employees working there. This would certainly benefit a large number of Indians earning their bread in U.S.A.

Concern over Naxalite menace in some parts of Uttar Pradesh

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, मैं आपकी अनुमति से विशेष उल्लेख के तहत पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीस गढ आदि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की ओर दिलाना चाहता हूं। इन क्षेत्रों में नक्सलवादियों ने अपनी समानांतर सत्ता कायम कर ली है। 20 नवंबर को इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौगढ़ में जायद (चंदौली) में बारूदी सुरंग से पी.ए.सी. के एक ट्रक को उड़ा दिया जिसमें 15 जवानों की घटना स्थल पर ही मौत हो गयी तथा दर्जनों की संख्या मे जवान जख्मी हो गए। इसके पूर्व 18 नम्बर को एक वन चौकी जयमोहनी जो कि नौगढ़ थाना क्षेत्र में पड़ती है, को डायनामाइट से उड़ा दिया था जिसमें वन दरोगा और दो सिपाही की मौत हो गयी थी। इन नक्सलवादियों द्वारा पुलिस पर आक्रमण, ग्रामीणों में दहशत बनाने और आधुनिक हथियार लूटने के लिए किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चंदौली, वाराणसी,मिर्जापुर,मऊ, बलिया, कुशीनगर, देवरिया, गाजीपुर आदि क्षेत्र नक्सली गतिविधियों से ज्यादा प्रभावित हैं। यहां के लगभग 350 गांवों और 28 थानों में इन नक्सली गुटों की ही सत्ता चलती है। नक्सली अपनी अदालतों लगाकर फैसला सुनाते हैं। उसका उल्लघंन करने पर मौत की सजा भी देते है। कोई भी पुलिसकर्मी रात में वर्दी पहनकर ड्यूटी करने की हिम्मत नहीं कर पाता है।

विंध्य की पहाडी से लगे नौगढ़, सोनभद्र के जंगलों में नक्सली गतिविधियां पिछले दो दशकों से जारी हैं। बिहार की सीमा से सटे वाराणसी का ग्रामीण हिस्सा चंदौली,सोनभद्र, मिर्जापुर में अब तक अपहरण, हत्या व लूट की सैंकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं जिससे स्थानीय निवासियों और ग्रामीणों मे भय व्याप्त है। लोग अपनी जमीन बेचकर शहर में मजदूरी करने और खानाबदोश जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हो रहे हैं।

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ताकि सरकार इन नक्सल प्रभावित (वाराणसी, नौगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर) क्षेत्रों के लिए एक विशेष कार्य योजना बनाकर इसे समाप्त करने की पहल करे।

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार): महोदय, मैं श्री मिश्र के इस विशेष उल्लेख के साथ **स्वयं** को सम्बद्ध करता हूं।

श्री कृपाल परमार (हिमाचल प्रदेश) : महोदय, मैं भी इस विशैष उल्लेख से सम्बद्ध करता हूं।

श्री शरद अनंत राव जोशी (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी इस विशेष उल्लेख से **स्वयं** को सम्बद्ध करता हूं।

Need for providing telephone facility at Machil in Kupwara district of Jammu and Kashmir

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ (Jammu and Kashmir): Mr. Deputy Chairman, Sir, we must feel rightly proud of our advancement in the field of telecommunications and information technology. But, then, the 'Ministry concerned must feel duty bound to ensure proper communication facilities in what are called 'backward areas'. Recently, I visited Machil in Kupwara District of Kashmir, and, to my horror, I found Machil, with a population of 10,000 people, without telephone facility. Machil remains, cut-off for.seven months from Kashmir valley and the plight of the people in the absence of any telecommunication link can be imagined. It is a tragedy that a small telephone exchange at Machil has not been provided all these years.

The Department of Telecommunications has not taken any notice of the fact that even the Army in that area is interested that telephone facility must be provided to the people of Machil. I was pleasantly surprised when a senior Army officer in Machil suggested that the telephone wiring could be provided through the poles and circuits that belong to the Army to make available this most important facility to the civilian population.

I strongly urge the Ministry of Telecommunications to visit Machil and ensure telephone facility there. The Chief General Manager of the circle should visit the area immediately, and, initiate measures to ensure the facility.

Demand to include the entire State of Andhra Pradesh in the National Food-for-Work Programme

SHRIMATI VANGA GEETHA (Andhra Pradesh):' Sir, my Special Mention is with regard to the request to include the entire State of Andhra